

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा०उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2017

विषय: देहरादून में नये जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स (Complex) के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में पुराने जेल परिसर में नया जिला न्यायालय के निर्माण हेतु एन०बी०सी०सी० द्वारा तैयार आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण कुल धनराशि रु० 206.78 करोड़ (रुपये दो सौ छः करोड़ अट्ठत्तर लाख) में से पूर्व स्वीकृत धनराशि रु० 26.6183 करोड़ (रुपये छब्बीस करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार) को घटाते हुए शेष धनराशि रु० 180.1617 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 77,17,000/- (रुपये सत्तहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर अनुबन्ध अथवा व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है। कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। आगणन का पुनरीक्षण का प्रयास नहीं किया जायेगा।
- (2) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- (3) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय। व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।
- (5) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (6) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (7) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2018 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-05-न्यायिक कार्य हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" से संलग्न अलॉटमेंट आई०डी० संख्या: S1707040464, दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या- 77/मतदेय/XXVII(5)/2017, दिनांक: 21 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आलोक कुमार वर्मा )  
प्रमुख सचिव ।

संख्या: 40-दो(8)/XXXVI(2)/2017-70/17, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून ।
4. परियोजना महाप्रबन्धक, एन०बी०सी०सी०, देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।
6. जिला न्यायालय आवासीय परिसर, बागेश्वर की निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सं० 30-दो(1)/06
7. जिला देहरादून में नये जिला न्यायालय कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सं० 17-दो(8)/14

आज्ञा से,

( महेश चन्द्र कौशिवा )  
अपर सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Law (S029)

आवंटन पत्र संख्या - 40-do(8)/2017

अलोटमेंट आई डी - S1707040464

अनुदान संख्या - 004

आवंटन पत्र दिनांक -21-Jul-2017

HOD Name - Registrar,Hon'ble High Court (4029)

1: लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन  
051 - निर्माण  
05 - न्यायिक कार्यों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास  
00 - k

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वहत निर्माण कार्य	7369000	7717000	15086000
	7369000	7717000	15086000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

7717000